BIYANI LAW COLLEGE
JAIPUR
Model Paper
B.A LL.B III semester

Semester – III Semester **Max Marks.70**
Subject – Economics-I

(Part A)

Answer the following question **2×5=10**

Q1. Define "State" under Article 12 of the Constitution of India.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "राज्य" की परिभाषा दीजिए।

Q2. What is meant by the Doctrine of Eclipse?

ग्रहण का सिद्धांत (Eclipse) से क्या अभिप्राय है?

Q3. State any two grounds on which reasonable classification under Article 14 is permissible.

अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्तिसंगत वर्गीकरण के कोई दो आधार बताइए।

Q4. What is the scope of Article 21A?

अनुच्छेद 21A का क्षेत्र (Scope) क्या है?

Q5. Mention any two Fundamental Duties under Article 51A.

अनुच्छेद 51A के अंतर्गत कोई दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

(Part B)

Answer any four questions 4×15 = 60

Q6. Explain the scope and importance of Judicial Review under Article 13. Discuss the doctrines of Severability and Waiver with the help of leading case laws.

अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रमुख वादों के संदर्भ में विभाज्यता (Severability) तथा परित्याग (Waiver) के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

Q7. Critically examine the Right to Equality under Articles 14 to 18. Discuss the principles of non-arbitrariness and reasonable classification with reference to judicial interpretations.

अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। न्यायिक व्याख्याओं के संदर्भ में मनमानी के निषेध तथा युक्तिसंगत वर्गीकरण के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

Q8. Analyze the scope of Article 19. Discuss the nature of freedoms guaranteed and the reasonable restrictions imposed upon them.

अनुच्छेद 19 के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। प्रदत्त स्वतंत्रताओं की प्रकृति तथा उन पर लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए।

Q9. Trace the constitutional interpretation of Fundamental Rights from A. K. Gopalan v. State of Madras to Kesavananda Bharati v. State of Kerala. Discuss how judicial interpretation shaped the doctrine of parliamentary supremacy and the emergence of the Basic Structure doctrine.

ए. के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास से केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल तक मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या का अनुगमन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि न्यायिक व्याख्या ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा मूल संरचना (Basic Structure) सिद्धांत के उद्भव को किस प्रकार प्रभावित किया।

Q10. Examine the Right against Exploitation and the Right to Freedom of Religion under Articles 23–28. How do these rights reflect the constitutional vision of social justice and secularism?

अनुच्छेद 23 से 28 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का परीक्षण कीजिए। ये अधिकार सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक अवधारणा को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं?

Q11. Discuss the significance of Article 32 as the “heart and soul” of the Constitution. Explain the role of Public Interest Litigation in enforcing Fundamental Rights.

अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय एवं आत्मा” क्यों कहा गया है, इस पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में जनहित याचिका (Public Interest Litigation) की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

Q12. Critically analyze the importance of Directive Principles of State Policy in the governance of the country. Are they merely non-justiciable guidelines, or have they acquired substantive constitutional significance through judicial interpretation?

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के शासन में महत्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या वे मात्र अविन्यायिक (Non-justiciable) दिशानिर्देश हैं, अथवा न्यायिक व्याख्या के माध्यम से उन्होंने वास्तविक संवैधानिक महत्व प्राप्त कर लिया है?

****